इकाई 5 ग्रामीण विकास का महत्व

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 परिचय

5.2 ग्रामीण विकास का महत्व

5.3 ग्रामीण विकास की जरूरत

5.4 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान

- 5.4.1 कृषि क्षेत्र का योगदान
  - 5.4.1.1 जीडीपी में योगदान
  - 5.4.1.2 रोजगार में योगदान
  - 5.4.1.3 औद्योगिक वस्तुओं के लिए कच्चे माल और बाजारों का स्रोत
  - 5.4.1.4 सस्ते और स्वस्थ भोजन तक पहुंच
- 5.4.2 गैर-कृषि क्षेत्र का योगदान
  - 5.4.2.1 रोजगार वृद्धि में योगदान
  - 5.4.2.2 जीडीपी में योगदान

5.5 ग्रामीण और सरकारी प्राथमिकताएं

- 5.5.1 कृषि उत्पादकता में सुधार
- 5.5.2 प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
- 5.5.3 ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार
- 5.5.4 ज्ञान सृजन की क्षमता को सुदृढ़ बनाना
- 5.5.5 भोजन तक पहुंच

5.6 विभिन्न हितधारक

- 5.6.1 सरकारी संगठन
- 5.6.2 पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई)
- 5.6.3 सहकारी समितियां
- 5.6.4 गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)

5.7 सारांश

5.8 संदर्भ

5.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप सक्षम होंगे कि :

- ग्रामीण भारत के विकास को बढ़ावा देने में ग्रामीण विकास के महत्व का विश्लेषण करने में;
- भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता को एक आवश्यकता के रूप में समझने में;
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र और गैर-कृषि क्षेत्र के योगदान की व्याख्या करनें में;
- खाद्य, कृषि और ग्रामीण विकास में कार्रवाई के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को परिभाषित करने में; और

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

- भारत में ग्रामीण विकास में लगे विभिन्न हितधारकों की भूमिका की रूपरेखा तैयार करने में।

5.1 परिचय

ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया के रूप में, एक घटना के रूप में, एक रणनीति के रूप में और एक अनुशासन के रूप में देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि उपक्षेत्र सबसे प्रमुख है। भारत के विकास का कोई भी कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो सकता है यदि वह ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा करता है। कई भौतिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, संस्थागत, संगठनात्मक और राजनीतिक कारक हैं जो ग्रामीण विकास के स्तर और गति को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि ग्रामीण विकास के लिए नीति के प्रत्येक उद्देश्य के लिए उपयुक्त उपकरणों की पहचान की जाए।

सभी संगठनों में, सरकार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कारक रही है और भविष्य में भी जारी रहेगी। सरकार की भूमिका अन्य एजेंसियों की भूमिकाओं को परिभाषित करने, उनकी गतिविधियों का समन्वय और विनियमन करने की होनी चाहिए। ग्रामीण विकास की बहुआयामी प्रकृति और विविध कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यान्वयन में लगी सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों की बड़ी संख्या भीड़ को देखते हुए विभिन्न – और अक्सर परस्पर विरोधी – उद्देश्यों के साथ कार्यक्रम, यह बिल्कुल आवश्यक है कि किसी क्षेत्र में संचालन में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को इष्टतम परिणामों के लिए एकीकृत और समन्वित किया जाए।

5.2 ग्रामीण विकास का महत्व

देश का प्रभावी विकास ग्रामीण समुदायों के भीतर हर पहलू के विकास में निहित है। इनमें स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, आवास, पर्यावरणीय परिस्थितियां और नागरिक सुविधाएं शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण भारत अभी भी अविकसित अवस्था में है। इसके पीछे का कारण कम साक्षरता दर, बेरोजगारी, गरीबी आदि है। ज्ञान की कमी और आधुनिक तकनीकों और विधियों को समझने में विफलता भी निम्न स्तर के जीवन के लिए जिम्मेदार है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम, योजनाएं और सरकार द्वारा गठित उपाय उनके जीवन को अधिक आरामदायक और आसान बनाने के लिए एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार देश के विकास में योगदान करते हैं। ये कार्यक्रम और योजनाएं ग्रामीण समुदायों की जीवन दशाओं में सुधार लाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पहचानने के बाद तैयार की जाती हैं।

भारत में ग्रामीण विकास का काफी महत्व है। भारत के विकास का कोई भी कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो सकता है यदि वह ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा करता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों की सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति को बढ़ाना है। इसे निम्नलिखित कारणों से महत्व मिला है:

ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के लिए भोजन, आश्रय, कपड़ा, रोजगार और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए समान अवसर पैदा करते हैं।

क) ग्रामीण विकास को महत्व मिला है क्योंकि यह व्यक्तियों के परिवर्तन के साथ आर्थिक विकास पर समान जोर देता है।

ख) यह विभिन्न कार्यक्रमों में व्यक्तियों और समुदायों की भागीदारी, योजना के विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों के बेहतर प्रवर्तन और ऋण तक बड़ी पहुंच को प्रोत्साहित करता है।

ग) ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपक्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18% का योगदान देता है। यह भारत के प्रमुख कृषि-उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा और कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है और औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार प्रदान करता है।

घ) ग्रामीण विकास ने कृषि क्षेत्र और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित करने में महत्व प्राप्त किया। गैर-कृषि क्षेत्र बेरोजगार ग्रामीण कार्यबल को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि अकेले कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार पैदा नहीं कर सकता है।

ङ) निरक्षरता सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधक है। ग्रामीण विकास ग्रामीण जनता को शिक्षित करने पर जोर देता है क्योंकि अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यूनेस्को ने 1964 में माना कि शिक्षा ही सशक्त माध्यम है जिसके साथ भारत अपना अगला स्वर्ण युग ला सकता है।

च) शहरी अभिजात वर्ग और ग्रामीण गरीबों के बीच असमानता को कम करने के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण है।

अपनी प्रगति की जाँच करें 1

1) ग्रामीण विकास के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) ग्रामीण विकास से आपका क्या तात्पर्य है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 ग्रामीण विकास की जरूरत

ग्रामीण विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। ग्रामीण विकास की आवश्यकता हरिजन के विकास में महात्मा गांधी के शब्दों में निहित है। उन्होंने 1936 में लिखा था कि:

भारत अपने कुछ शहरों में नहीं बल्कि इसके 7,00,000 गांवों में पाया जाता है, लेकिन शहरवासियों का मानना है कि भारत अपने कस्बों में पाया जाता है और गांव हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। हम शायद ही यह पूछने के लिए रुके हैं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों के उन गरीब लोगों को खाने और खुद को अच्छी तरह से कपड़े पहनने की पर्याप्त आवश्यकता है और क्या उनके पास धूप और बारिश से खुद को आश्रय देने के लिए छत है।

इसलिए, ग्रामीण विकास भारत में एक परम और तत्काल आवश्यकता है। ग्रामीण विकास की आवश्यकता पर पांच व्यापक श्रेणियों के तहत चर्चा की गई है:

1) **बुनियादी सुविधाओं का विकास:** स्वस्थ और उत्पादक जीवन के लिए और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें उचित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों, पानी की आपूर्ति, सिंचाई सुविधाओं, पुलों और बाजारों जैसी बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों को समग्र विकास के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है। सतत ग्रामीण विकास के लिए नए बुनियादी ढांचे के निरंतर प्रावधान और मौजूदा बुनियादी ढांचे के रखरखाव की आवश्यकता है।

2) **गरीबी उन्मूलन:** चूंकि अधिकांश गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रम मजदूरी और स्वरोजगार के अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित हैं। सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों, ग्रामीणों, पंचायतों, उद्योगों आदि सहित एक एकीकृत दृष्टिकोण। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच गरीबी असंतुलन को कम करने के लिए आवश्यक है।

3) **स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास:** ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की प्रणाली ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ग्रामीणक्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर ऊंची बनी हुई है। ग्रामीण भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की कमी और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की कमी देखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

4) **उत्पादक और मानव संसाधन का विकास:** दुर्गम-दुष्कर ग्रामीण क्षेत्र हमारी प्रमुख चिंता का विषय हैं। कार्यबल की गुणवत्ता और उत्पादक संसाधनों का विकास सतत ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख निर्धारक हैं। यह साक्षरता दर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि में सुधार करके किया जा सकता है।

5) **शिक्षा और रोजगार:** शिक्षा को लंबे समय से ग्रामीण विकास के लिए एक संभावित साधन के रूप में मान्यता दी गई है। यह लोगों को आर्थिक रूप से जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण विकास और शैक्षिक विकास अविभाज्य हैं। ग्रामीण कार्यबल के लिए रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

5.4 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान

भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण चरित्र में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण भारत में देश की आबादी का दो तिहाई हिस्सा शामिल है और राष्ट्रीय आय में इनका आधा हिस्सा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करने वाले सबसे बड़े घटकों में से एक कृषि है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। तथापि, कृषि से गैर-कृषि कार्यकलापों की ओर धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है और इस प्रकार ग्रामीण लोग गैर-कृषि कार्यकलापों से भी अपनी आय प्राप्त करते हैं। कृषि क्षेत्र में कृषि और संबद्ध आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। कृषि क्षेत्र का एक हिस्सा, गैर-कृषि क्षेत्र भी लघु ग्रामोद्योग, ग्रामीण शिल्प आदि के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5.4.1 कृषि क्षेत्र का योगदान

भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान समाज है। कृषि और संबंधित गतिविधियां देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 60% आबादी अभी भी आजीविका और अस्तित्व के लिए कृषि पर निर्भर है।

5.4.1.1 जीडीपी में योगदान

ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत सरकार की नजर कृषि से 1 ट्रिलियन डॉलर के योगदान पर है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने 2019 में सकल घरेलू उत्पाद में 15.96% का योगदान दिया। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा घट रहा है, हालांकि, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र उच्च दर से विस्तार कर रहे हैं।

5.4.1.2 रोजगार में योगदान

ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र की वृद्धि भारत की लगभग आधी आबादी के लिए आजीविका और रोजगार के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करती है। भारत में, कुल आबादी (2014 में) का लगभग 47% में) अन्य देशों की तुलना में कृषि से अपनी आय प्राप्त करता है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत करके आजीविका और रोजगार प्रदान करने में मदद करता है।

5.4.1.3 कच्चे माल का स्रोत और औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार

चीनी, जूट, कपास, खाद्य तेल, चमड़ा और तंबाकू जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल का प्रमुख स्रोत कृषि से प्राप्त होता है। कई अन्य उद्योग भी अपने विकास के लिए कृषि पर निर्भर हैं। ग्रामीण विकास इन अग्रणी उद्योगों के प्रभावी और कुशल विकास के लिए ऐसी सामग्रियों की गुणवत्ता और प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है जो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र कई औद्योगिक वस्तुओं, जैसे कीटनाशकों, पोल्ट्री फीड आदि के लिए एक अच्छा और तैयार बाजार भी प्रदान करते हैं। यह कई उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक तैयार बाजार भी प्रदान करता है।

5.4.1.4 सस्ते और स्वस्थ भोजन तक पहुंच

आर्थिक विकास भोजन की मांग में पर्याप्त वृद्धि की विशेषता है। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों, लाइव-स्टॉक और समुद्री भोजन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। विविध जलवायु परिस्थितियों और एक लंबी तटरेखा ने एक प्रमुख खाद्य उत्पादक के रूप में भारत की स्थिति में योगदान दिया है। यदि हम डेयरी/दुग्ध उत्पादन को देखें, तो भारत दुनिया में शीर्ष दूध उत्पादक देश है।

5.4.2 गैर-कृषि क्षेत्र का योगदान

यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही एकमात्र व्यवसाय था, तो इसका मतलब यह होगा कि देश के बाकी हिस्सों की तुलना में ग्रामीण आय में वृद्धि नहीं हो सकती है। भले ही कृषि ग्रामीण परिदृश्य पर हावी है, लेकिन यह वहां की एकमात्र आर्थिक गतिविधि नहीं है। चूंकि कृषि के विस्तार के लिए उपलब्ध भूमि तेजी से दुर्लभ हो जाती है, इसलिए यदि ग्रामीण गरीबी को गहराने से बचना है तो गैर-कृषि रोजगार के अवसरों का विस्तार होना चाहिए। गैर-कृषि क्षेत्र देश के तेज आर्थिक विकास की कुंजी रखता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आय बढ़ाने की क्षमता है।

5.4.2.1 रोजगार वृद्धि में योगदान

गैर-कृषि क्षेत्र बेरोजगार ग्रामीण कार्यबल के लिए रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तिहाई से अधिक ग्रामीण श्रमिक गैर-कृषि कार्य में लगे हुए पाए गए। इसने पिछले दो दशकों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि में वृद्धि की है। बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश और गरीबी में कमी से गैर-कृषि विकास को बढ़ावा मिला। श्रम का आकस्मिककरण गैर-कृषि रोजगार की एक विशेषता है। वे आमतौर पर अकुशल दैनिक वेतन भोगी नौकरियां हैं। हाल के वर्षों में कैजुअल मजदूरों की मजदूरी सबसे तेज गति से बढ़ी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण आकस्मिक मजदूरी दर को ऊपर की ओर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5.4.2.2 सकल घरेलू उत्पाद में योगदान

कृषि क्षेत्र की तुलना में हाल के वर्षों में ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक तिहाई का योगदान देता है, जबकि कृषि की इसी अवधि में गिरावट आई है। यह देखा गया है कि गैर-कृषि क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए दबाव और खिंचाव ताकतें जिम्मेदार हैं। दबाव पुश फैक्टर तब काम करता है जब श्रमिक खुद को कृषि उपज से घरेलू जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ पाते हैं, इस प्रकार घरेलू आय बढ़ाने के लिए वे खुद के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में गैर-कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां उन्हें फसल की विफलता का खतरा भी नहीं है। खिंचाव बल (पुल फोर्स) यानी शहरीकरण को गैर-कृषि विकास के लिए एक प्रमुख प्रेरक के रूप में पहचाना गया है। यह क्षेत्र औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अपनी प्रगति की जाँच करें 2

1) ग्रामीण विकास की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास के संबंध को स्पष्ट कीजिये।

.....

.....

.....

.....

.....

5.5 ग्रामीण और सरकारी प्राथमिकताएं

तेजी से शहरीकरण के बावजूद, भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच-यानी बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, सड़कें और बिजली- शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पीछे हैं। शहरी-पूर्वाग्रह द्वारा बनाई गई इस असमानता ने आर्थिक विषमताओं को जन्म दिया है जो ग्रामीण आबादी को एक बड़े नुकसान में डालते हैं और युवा और कुशल लोगों को शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन हानिकारक आर्थिक और बुनियादी ढांचे की स्थितियों के कारण, (i) कृषि उत्पादकता आर्थिक क्षमता की तुलना में बहुत कम है, (ii) कृषि श्रम और निवेश पर रिटर्न गैर-कृषि उद्यमों की तुलना में बहुत कम है, (iii) कृषि और ग्रामीण उद्यमों में निजी निवेश बहुत कम है और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण द्रव्यमान पैदा नहीं करता है, (iv) आधुनिक तकनीक को अपनाना धीमा है, (v) कृषि उत्पादन की लागत अधिक है, (vi) कटाई के बाद नुकसान अधिक है, और (vii) ग्रामीण-से-शहरी पलायन अन्यथा की तुलना में बहुत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक केंद्रित और संतुलित विकास इन परिस्थितियों को धीमा करेगा और इन प्रवृत्तियों को उलट देगा जो पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण लाभ उत्पन्न करेगा।

प्रत्येक समुदाय के सतत विकास को रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध और निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान स्थिति से भविष्य में वांछनीय स्थिति की ओर बढ़ सके। सतत विकास में विभिन्न विकास पहलुओं का समन्वय और कुछ क्षेत्रों (सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय) के कार्यक्रमों में विरोधी उद्देश्य भी शामिल हैं। ग्रामीण गरीबों के विकास के लिए कार्रवाई के लिए सरकारी प्राथमिकताओं के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

5.5.1 कृषि उत्पादकता में सुधार

किसानों की आय में सुधार के लिए कृषि उत्पादकता में सुधार करना महत्वपूर्ण है, और इसके लिए उपज में वृद्धि, संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से बेहतर उत्पादकता, फसल के नुकसान में कमी के साथ और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसानों को उत्पादन के लिए उचित मूल्य मिले। इस प्राथमिकता वाले क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, ग्रामीण जीवन स्तर को बढ़ाना, बाजार पहुंच में सुधार करना और कृषि व्यवसाय का समर्थन करना है।

बीजों तक पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने से अभूतपूर्व लाभ उन नीतियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को उजागर करते हैं जो किसानों के लिए सबसे अधिक लाभ हासिल करेंगे। प्राथमिक उपकरण नई प्रौद्योगिकियों का बढ़ता उपयोग, सदस्यों और उप-क्षेत्रों को तकनीकी सहायता, कृषि व्यवसाय और क्षमता निर्माण के लिए समर्थन का लक्ष्य भारत में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए मुख्य रणनीतियां मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, बारिश के माध्यम से आपूर्ति जल संचयन, वित्तीय वितरण प्रणाली में दक्षता में सुधार, कृषि प्रणाली उन्मुखीकरण की आवश्यकता, बाजार सुधार की आवश्यकता आदि में सुधार करना है।

5.5.2 प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

प्राकृतिक संसाधन ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमि, जल, पौधे और पशु आनुवंशिक संसाधन कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी को खाद्य उत्पादन और ग्रामीण विकास में योगदान करने में सक्षम बनाते हैं। उन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, वित्तीय पूंजी, श्रम, बुनियादी ढांचे और संस्थानों के साथ जोड़ने से उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है।

ग्रामीण समुदाय, विशेष रूप से, प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते उपयोग से बहुत प्रभावित होते हैं। उनमें से कई के लिए, विकास उत्पादकता और धन के संचय को बढ़ाने के बजाय आजीविका और अस्तित्व महत्वपूर्ण है। ग्रामीण समुदायों की रहने की योग्यता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन ही एकमात्र तरीका प्रतीत होता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विभिन्न हितधारकों से सहयोगात्मक कार्यों की आवश्यकता होती है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और गैर-उपयोग सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए सरकारी दृष्टिकोण में ऐसी प्रथाएं शामिल हैं जोः जल स्रोतों की सुरक्षा और बहाली को प्रोत्साहित करें, और जल उपयोग अनुकूलन को बढ़ावा दें। पुनः उपयोग या निपटान से पहले अपशिष्ट जल उपचार के लिए प्रणालियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना और कार्बन स्टॉक में सुधार करना। कचरे में कमी, रीसाइक्लिंग और जिम्मेदार निस्तारण को बढ़ावा देना।

5.5.3 ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार

कृषि और ग्रामीण विकास का समर्थन करने और कृषि उपज के लिए प्रभावी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की सुविधा के लिए उपयुक्त भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की उपस्थिति एक मुख्य आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों, पटरियों, पुलों, सिंचाई योजनाओं, पानी की आपूर्ति, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और बाजारों जैसी

बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों की आवश्यकता होती है ताकि स्थानीय आबादी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके और सामाजिक और आर्थिक उत्पादक जीवन जी सके। स्थानीय संसाधन आधारित दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों (विशेष रूप से ग्रामीण सड़कों) में बुनियादी ढांचे के प्रभावी और टिकाऊ प्रावधान के लिए रणनीतियों और तरीकों को अब बड़ी संख्या में सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों द्वारा अपनाया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुधार के लिए ऐसे दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता की स्पष्ट मान्यता है।

भारत में अकब चल रहे प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पीयूआरए) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) हैं। नाबार्ड के तहत आरआईडीएफ का निर्माण ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के सरकार के प्रयास में एक प्रमुख मील का पत्थर था। बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण होने के बावजूद, भारतीय राज्यों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भारी कमियां बनी हुई हैं। बुनियादी सुविधाओं की मात्रा और गुणवत्ता काफी हद तक शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम है जनसंख्या का अपेक्षाकृत कम घनत्व, कम घरेलू आय और पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं की अनुपस्थिति को ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए चुनौतियां माना जाता है।

5.5.4 ज्ञान सृजन की क्षमता को सुदृढ़ बनाना

ऑन-फार्म निवेश के माध्यम से आजीविका और खाद्य सुरक्षा में तेजी से सुधार को बढ़ावा देने में सफलता छोटे पैमाने पर उन किसानों पर निर्भर करती है जिनकी प्रासंगिक ज्ञान तक अच्छी पहुंच है। इसके लिए प्रभावी ज्ञान सृजन और प्रसार प्रणालियों के प्रावधान की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य किसानों, कृषि शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विस्तार श्रमिकों और संचारकों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।

कृषि विस्तार की प्रभावशीलता में सुधार में आमतौर पर सेवाओं के विकेंद्रीकरण का समर्थन करना और उन्हें किसानों की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना शामिल है। इसके लिए न केवल सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं, बल्कि गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं सहित बहु-सेवा प्रदाताओं के उद्भव के लिए परिस्थितियां बनाने की आवश्यकता है। भूख-रोधी कार्यक्रम के संबंध में शिक्षा में क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण लोगों की बुनियादी शैक्षिक आवश्यकताओं पर जोर देने की आवश्यकता है, जिसमें सतत कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित सभी तकनीकी विषयों को शामिल किया गया है। यद्यपि बड़ी संख्या में कारक इस तरह की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं और स्थिति में सुधार के लिए कई दृष्टिकोण और रणनीतियां अपनायी जाती रही हैं, लेकिन ज्ञान प्रबंधन की कमी हमें एक कारण प्रतीत होता है कि अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागत प्रभावी ढंग से डिजाइन नहीं किया गया है और न ही प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया है।

5.5.5 भोजन तक पहुंच

भारत में वर्तमान में दुनिया में कुपोषित लोगों की सबसे बड़ी संख्या है और यह इस तथ्य के बावजूद है कि देश ने पिछले दशकों में स्वास्थ्य निर्धारकों में पर्याप्त प्रगति की है और कृषि उत्पादन में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। स्वस्थ और

किफायती भोजन तक पहुंच प्राप्त करना ग्रामीण निवासियों के लिए एक चुनौती हो सकती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य खुदरा विक्रेताओं की कमी है और उन्हें खाद्य रेगिस्तान यानी ताजा, किफायती खाद्य पदार्थों की सीमित आपूर्ति वाले क्षेत्र माना जाता है। खाद्य सुरक्षा भारत में विकास के प्रमुख उद्देश्यों में से एक रहा है। यद्यपि भारत में पर्याप्त खाद्य उत्पादन है, फिर भी यह उपलब्धि घरों तक नहीं पहुंच पाई।

अपनी प्रगति की जाँच करें 3

1) ग्रामीण और सरकारी प्राथमिकताओं का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

5.6 विभिन्न हितधारक

ग्रामीण भारत में देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने की उच्च क्षमता है। हालांकि सरकार ने विभिन्न योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन की स्थिति को बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन विकास की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। ग्रामीण भारत की सतत वृद्धि और विकास के लिए बहुहितधारकों की भागीदारी बहुत आवश्यक है।

जमीनी स्तर की योजना किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। कई भौतिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, संस्थागत, संगठनात्मक और राजनीतिक कारक हैं जो ग्रामीण विकास के स्तर और गति को प्रभावित करते हैं। इसका तात्पर्य सभी स्तरों घर, गांव, जिला, राज्य और राष्ट्र पर नियोजन से है। जमीनी स्तर की योजना बनाने और इसके बेहतर परिणामों के लिए हितधारकों को शामिल करके उपयुक्त भागीदारी पद्धति के माध्यम से आवश्यक डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। भारत में ग्रामीण विकास में लगे विभिन्न हितधारकों को संक्षेप में निम्नानुसार वर्णित किया गया है:

5.6.1 सरकारी संगठन

देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम और योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत सहित सभी विकासशील देशों में सरकार ग्रामीण विकास के

लिए एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में कार्य करती है। सार्वजनिक नौकरशाही सभी प्रकार के विकास को पूरा करने के लिए राज्य की सभी जिम्मेदारी निभाती है। सरकार की प्राथमिक भूमिका ऐसे संस्थानों की स्थापना करना है जो बेहतर परिणामों के लिए सभी सुविधाएं और आवश्यक सहायता प्रदान करें। सरकारी संगठनों के मुख्य कार्यों को निम्नलिखित छह स्तरों पर देखा जा सकता हैः

क) नीति निर्माण को सुविधाजनक बनाना;

ख) विभिन्न आर्थिक एजेंटों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन का समन्वय करना;

ग) सामूहिक कार्रवाई और स्व-विनियमन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना;

घ) नियमों और नीतियों को लागू करना;

ङ) संघर्षों को हल करना और मध्यस्थता प्रदान करना;

च) तकनीकी सहायता प्रदान कर।

भारत में ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संगठनों का उद्देश्य गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाना है। कुछ ऐसे संगठन जिन्होंने भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के विकास और कल्याण में बहुत योगदान दिया है, वे हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि। ये संगठन आजीविका के अवसर, बीपीएल परिवारों को बुनियादी आवास, बुजुर्गों को सामाजिक सहायता, क्षमता विकास और प्रशिक्षण, स्वैच्छिक एजेंसियों की भागीदारी को बढ़ावा देने, ग्रामीण कनेक्टिविटी आदि प्रदान करने के लिए काम करते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम हैंः मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)), सभी के लिए आवासः बीपीएल परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सामाजिक पेंशन के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) भूमि की उत्पादकता में सुधार के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन और एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)

5.6.2 पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई)

पंचायती राज संस्थाओं को 1992 में भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पेश किया गया है। पंचायती राज संस्था योजनाओं के विकास और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए मुख्य विकेंद्रीकृत संस्था है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से, ग्रामीण विकास में ग्रामीण अवसंरचना में सुधार, ग्रामीण परिवारों की आय में सुधार और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तंत्र से संबंधित वितरण प्रणालियों के उपाय शामिल हैं। यह गांधी जी ही थे जिन्होंने ग्रामीण विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में ग्राम पंचायतों के महत्व को महसूस किया, और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और पोषित किया। आजादी के बाद भारत में ग्रामीण विकास में पंचायतों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है।

जनवरी 1957 में, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के कामकाज का अध्ययन करने और यह सुझाव देने के लिए कि इसे सर्वोत्तम तरीके से कैसे बनाए रखा जा सकता है और कार्यान्वित किया जा सकता है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति ने स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की, जहां ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों और जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया जाना था। योजनाओं के कार्यान्वयन और समुचित आर्थिक विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियां और उत्तरदायित्व प्रदान किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का कार्यान्वयन स्थानीय पहल और विकासात्मक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर देने के लिए था। देश का भविष्य वास्तव में प्रभावी पंचायती राज और लोगों की भागीदारी या सहयोग पर निर्भर करता है। यह एकमात्र प्रभावी साधन है जो हमारी नियोजन प्रक्रिया में गति और मजबूती डाल सकता है और उत्पादकता के लिए देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

25 दिसम्बर, 2002 को पेयजल क्षेत्र के अंतर्गत पंचायतों को पेयजल परियोजनाएं तैयार करने, कार्यान्वित करने, प्रचालन करने और अनुरक्षण करने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल 'स्वजल धारा' शुरू की गई थी। विकास प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक शामिल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27 जनवरी, 2003 को एक नई पहल हरियाली शुरू की गई थी। हरियाली को वाटरशेड विकास कार्यक्रमों अर्थात् आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी और डीडीपी के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने और शामिल करने के लिए शुरू किया गया था।

5.6.3 सहकारी समितियां

एक सहकारी संगठन भारत सहित विकासशील देशों में व्यापक रूप से प्रचलित है। इसमें ग्रामीण विकास के साधन के रूप में अपार संभावनाएं हैं। एक सहकारी संगठन को आम तौर पर अपनी सामान्य सामाजिक और आर्थिक जरूरतों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों के एक स्वायत्त संघ के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार, एक सहकारी संगठन एक ऐसा सामाजिक-आर्थिक संगठन है जिसके सदस्य अपनी रूचियों के साथ वास्तव में दिल से इसके साथ संबद्ध होते हैं। यह अपने स्वयं के कुछ मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है, जो इसे संगठनों के अन्य रूपों से अलग करते हैं।

23 सितंबर, 1995 को मैनचेस्टर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) कांग्रेस ने निम्नलिखित सात सिद्धांतों को अपनायाः

i) स्वैच्छिक और खुली सदस्यता;

ii) लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण;

iii) सदस्य आर्थिक भागीदारी और साझा पूंजी पर सीमित ब्याज;

iv) स्वायत्तता और स्वतंत्रता;

v) सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना का प्रावधान;

vi) सहकारी समितियों के बीच सहयोगय और

vii) समुदाय के लिए चिंता।

कुप्रबंधन के कारण अधिकांश ग्रामीण सहकारी समितियां वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं हैं। सहकारी समितियों को भारत की नयी आर्थिक नीति (जिसमें विनियमन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण शामिल हैं) में बने रहना है तो इनके संचालन के लिये पेशेवर प्रबंधकों की आवश्यकता महसूस होती है।

5.6.4 स्वैच्छिक एजेंसियां/गैर सरकारी संगठन

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) लोगों की जरूरतों और शिकायतों की अभिव्यक्ति के लिए व्यवहार्य ताकतों के रूप में उभरे हैं। भारत में एनजीओ कोई नई बात नहीं है। स्वैच्छिक प्रयास हमेशा भारतीय संस्कृति और सामाजिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लोगों को मान्यता प्राप्त संघों में संगठित करने और ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी और भागीदारी की आवश्यकता को अब पूरी तरह से मान्यता दी गई है। हाल के वर्षों में, इनकी संख्या काफी बढ़ी है और इन्होंने अधिक महत्व प्राप्त किया है और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए हैं क्योंकि सरकारी संगठन लोगों (विशेषकर वांछित स्तर पर ग्रामीण विकास के संबंध में ग्रामीण गरीब तक) तक पहुंचने में सक्षम नहीं है विकास का कार्य इतना बड़ा और जटिल है कि समस्या को ठीक करने के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए, विभिन्न विभागों, एजेंसियों और यहां तक कि गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। इतनी बड़ी आवश्यकता के कारण, भारत में गैर-सरकारी संगठनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान में, भारत में लगभग 25,000 से 30,000 सक्रिय गैर-सरकारी संगठन हैं।

हर पंचवर्षीय योजना की तरह, भारत के ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ रही है, इसलिए गैर-सरकारी संगठन अब विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को आकर्षित कर रहे हैं। गैर-सरकारी संगठन विकास योजनाओं के योजनाकारों और कार्यान्वयनकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। वे विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानीय संसाधनों को जुटाने में मदद करते हैं। गैर-सरकारी संगठन आत्मनिर्भर और टिकाऊ समाज के निर्माण में मदद करते हैं। ये एजेंसियां लोगों और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। गैर-सरकारी संगठन वास्तव में विकास, शिक्षा और व्यावसायिकरण के सुविधाप्रदाता हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (कपार्ट) ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और सहायता करना है। कपार्ट निम्नलिखित योजनाओं के तहत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है:

1) ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देना
2) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास
3) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)
4) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी)
5) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिये लाभार्थियों का संगठन
6) मनरेगा और एनआरएलएम

7) ग्रामीण प्रौद्योगिकी योजना की उन्नति (आर्ट्स)

8) पंचायती राज

9) विकलांग लोगों का पुनर्वास।

गैर-सरकारी संगठनों को ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने और प्रशिक्षण देने, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को सूचीबद्ध करने और उनके साथ मिलकर काम करने में संगठनों के अन्य रूपों पर विशेष लाभ है।

अपनी प्रगति की जाँच करें 4

1) पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण विकास के बारे में बतायें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) स्वैच्छिक एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

5.7 सारांश

इस इकाई ने आपको भारत में ग्रामीण विकास के महत्व के बारे में कुछ विचार दिया होगा। जैसा कि आप अब तक जानते हैं कि भारत के विकास का कोई भी कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो सकता है यदि वह ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा करता है। शहरी अभिजात वर्ग और ग्रामीण गरीबों के बीच असमानता को कम करने के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण है। इसलिए, ग्रामीण विकास भारत में एक परम और तत्काल आवश्यकता है। तेजी से शहरीकरण के बावजूद, भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच- यानी बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, सड़कें और बिजली- शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पीछे हैं। ग्रामीण भारत में देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने की उच्च क्षमता है। लेकिन विकास की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। जमीनी स्तर की योजना बनाने के लिए, बेहतर परिणामों के लिए हितधारकों को शामिल करके उपयुक्त भागीदारी पद्धति के माध्यम से आवश्यक डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। भारत में ग्रामीण विकास में लगे विभिन्न हितधारक सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्थान, सहकारी समितियां हैं।

5.8 संदर्भ

सिंह, के। ग्रामीण विकासः सिद्धांत, नीतियां और प्रबंधन। सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लि. लिमिटेड

माथुर, ए। 2005. ग्रामीण विकासः सूचकांक और लिंकेज। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

सतीश, पी। ग्रामीण बुनियादी ढांचा और विकासः एक सिंहावलोकन। *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स,* 62 (1): 32-51

सिंह, होशियार, एड। भारत में ग्रामीण विकासः नीतियों और कार्यक्रमों में मूल्यांकन अध्ययन। जयपुरः प्रिंटवेल पब्लिशर्स।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY